निजीकरण की मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीति के खिलाफ एकजुट हों!

एक पर हमला सब पर हमला!

निम्नलिखित के द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति:

ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIPNBOA),

ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA),

सेंट्रल रेलवे ट्रैकमेनटेनर्स यूनियन (CRTU),

कामगार एकता कमिटी (KEC),

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (MSEWF),

पुणे जिला बैंक एम्प्लोईस एसोसिएशन (PDBA),

सबोर्डीनेट इंजीनीयर्स एसोसिएशन (MSEB)

9 जून 2022

1991 में उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से, केंद्र और अधिकांश राज्यों में विभिन्न सरकारें भारतीय और विदेशी दोनों बड़े कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए उस नीति को लागू करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ कामगारों के विभिन्न संगठन शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। देश भर में और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण विभिन्न रूपों में और विभिन्न नामों (जैसे निगमीकरण, विनिवेश, आउटसोर्सिंग, संविदाकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, भूमि सहित संपत्ति का मुद्रीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, आदि) के तहत लागू किया जा रहा है।

निजीकरण न केवल संबंधित श्रमिकों के हितों के खिलाफ है, बल्कि वह उन सभी लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो उस उद्यम की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। निजीकरण से अधिकतम मुनाफा बनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जो सभी उपयोगकर्ताओं के हितों के विरुद्ध है।

यह जानकर खुशी होती है कि देश भर से रेलवे, बिजली, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, रक्षा उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, इस्पात, कोयला और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता एक साथ आए हैं और भारतीय लोगों के जीवन और आजीविका पर केंद्र और राज्य सरकारों के हमलों के खिलाफ बहुत साहस और दृढ़ विश्वास के साथ लड़ रहे हैं।

वे आश्वस्त रूप से तर्क दे रहे हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें निजी मालिकों के लिए अधिकतम लाभ के उद्देश्य से चलाया जा सकता है। यह संदेश हमें सभी लोगों तक पहुंचाना है, क्यों कि सभी निजीकरण के विनाशकारी परिणाम भुगतने जा रहे हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में कामगारों और लोगों के संगठन इन हमलों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार करने और निजीकरण को रोकने की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं।

हम स्थिति का जायजा लेने और संघर्ष को आगे बढ़ाने के एक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए रविवार, 12 जून 2022 को शाम 5:30 बजे पत्रकार भवन, पुणे में बैठक कर रहे हैं।

हम आपको इस बैठक को अपने सम्मानित मीडिया में प्रचारित करने और इस बैठक में शामिल होने के लिए बहुत सौहार्दपूर्ण रूप से आमंत्रित करते हैं!